

खबर मन्त्र

नामकुम के बड़ाम गांव में सीएम ने किया समावेशी न्याय सदन का उद्घाटन, कहा समावेशी विकास से अंत्योदय संभव

स्वच्छ भारत मिशन ने चलाया अभियान नामकुम : मुख्य न्यायाधीश भी स्वच्छता के बंधन में बंधे

लोकतंत्र की सफलता में सबकी भूमिका अठम

उत्तर मन् बट्टी

संघी लोकतंत्र प्रणाली के अर्थ है कि 'सामूहिकता, विनिश्चय और अंत्योदय' के परमार्थ में विकास को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ है। ही राम शिखर की जिम्मे को बड़ाम गांव में समावेशी न्याय सदन का उद्घाटन का रहे में। उन्होंने कहा कि भारत के हर गांव को गांव के रूप में ही आत्मनिर्भर है। उन्होंने कहा कि एक संभव समाज का दिन है। समाज केवल एक ही दिशा में ही बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि समाज के विकास के लिए हमें सबकी भूमिका अठम देना आवश्यक है।



कमलेशी न्याय सदन का उद्घाटन करते सीएम, चीफ जस्टिस ने अन्य

कमलेशी न्याय सदन की उद्घाटन करते सीएम, चीफ जस्टिस ने अन्य लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र की सफलता में सबकी भूमिका अठम है। उन्होंने कहा कि समाज के विकास के लिए हमें सबकी भूमिका अठम देना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि समाज के विकास के लिए हमें सबकी भूमिका अठम देना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि समाज के विकास के लिए हमें सबकी भूमिका अठम देना आवश्यक है।



अंत्योदय कार्य समारोह शुरू की एक प्रदान करते सीएम और अन्य

लोकतंत्र की सफलता में सबकी भूमिका अठम है। उन्होंने कहा कि समाज के विकास के लिए हमें सबकी भूमिका अठम देना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि समाज के विकास के लिए हमें सबकी भूमिका अठम देना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि समाज के विकास के लिए हमें सबकी भूमिका अठम देना आवश्यक है।



सीएम ने स्वच्छता अभियान के अंत्योदय कार्य समारोह में भाग लिया

स्वच्छ भारत मिशन ने चलाया अभियान नामकुम : मुख्य न्यायाधीश भी स्वच्छता के बंधन में बंधे। उन्होंने कहा कि स्वच्छता के बंधन में बंधे। उन्होंने कहा कि स्वच्छता के बंधन में बंधे। उन्होंने कहा कि स्वच्छता के बंधन में बंधे।



the pioneer

www.dailypioneer.com


the pioneer

RANCHI | MONDAY | AUGUST 27 2018

townhall 03

3 wings of democracy must respect each other: CM

Benefits of schemes worth ₹75 crore distributed among 20 L people

PKS ■ RANCHI

State government on Sunday provided benefits of government schemes to 20 lakh people of State during a legal empowerment camp held in Jagatoli village near Capital city on Sunday. The benefits worth Rs 75 crores were provided under various heads including scholarship, victim compensation, scheme and other social welfare schemes.

Chief Minister Raghubar Das inaugurated the legal empowerment camp in the presence of Deputy Speaker of Rajya Sabha Hariyansh, Chief Justice of Jharkhand High Court Anirudha Bose, Rajya Sabha MP Primal Nathwani and other dignitaries.

The CM also inaugurated Samwadi Nyay Kendra which is a unit to give judicial and executive services at the village level in the function.

Addressing the gathering Das said there was need for coordination among the three wings of democracy for providing benefit to the people. He said the legislature, judiciary and the executive should respect each other.

The CM said that many poor people particularly the tribals were unable to get benefits of the governmental schemes due to lack of awareness.

He mentioned that government would launch health insurance scheme on September 25, the birth anniversary of Pandit Deen Dayal Upadhyaya, with the aim to cover 27 lakh families under the plan. He expressed hope that Nyay Kendra would spread awareness about the schemes among the rural people.

Speaking on the occasion, deputy speaker of Rajya Sabha Hariyansh stated that the Nyay Kendra would help provide quality justice to the people. He added that legal empowerment camp was being held on rotation mode in the State adding that it has been organized at four places in state earlier.

Chief Justice of Jharkhand High Court Anirudha Bose said now the courts are taking the legal services to doors of the people. "Legal service movement which has been structured through legal services authorities come in as the courts with the prevailing number of judges and the number of litigation and grievances could not conclude all the litigations within a reasonable period of time," he said.

He said that JHALSA was one of the best performing legal service organizations in the country. Justice Bose opined now court was trying to take justice to people instead of peo-



Chief Minister Raghubar Das (center) Chief Justice of Jharkhand High Court Anirudha Bose (right) handing over appointment letter to Manoj Mehta during inauguration of the Government Nyay Kendra at Jagatoli village near Ranchi on Sunday. Deputy Speaker of Rajya Sabha Hariyansh, Justice DN Patel and others are also seen in the picture.

ple coming to the court adding that Nyay Kendra was one of the

means to achieve it. "Court should be accessible to all. Society would law if everyone does not think that law is there for them. All are equally protected by law," he

added.

MP Primal Nathwani requested the CM to take steps for starting the school in the village whose building was completed long ago. Justice DN Bose detailed on the works of the Nyay Kendra and the legal empowerment camps.

The CM, Hariyansh and Justice Bose jointly transferred scholarship worth Rs 18.60 crore to 1,60,595 students through direct benefit transfer scheme in the function. Among the beneficiaries were victims of UNV violence who were provided jobs and cash compensation.

Judges of high court including Justice HC Mishra, Justice SN Pathak, Justice AE Choudhary Justice Anil Kumar Rawat Choudhary, Justice Ratnakar Bhargava, Justice Rajesh Shankar, Justice JB Mangalmeeti, Registrar General Anil Nath and District officials were present at the function.

दैनिक भास्कर

विधिक सेवा सशक्तीकरण शिविर व समावेशी न्याय सदन का सीएम ने किया उद्घाटन

झारखंड से शुरू होगी दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना

पॉलिटिकल रिपोर्टर | राठी

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि पीठित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर 25 नवंबर को पूरे देश में प्रधानमंत्री आरोग्य योजना 'असुखान भारत' शुरू होगी। झारखंड सरकार का प्रयास है कि दुनिया की सबसे बड़ी इस स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तों झारखंड से हो। इससे राज्य के 57 लाख परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। किसी भी गरीब की दवा के अभाव में मौत नहीं होगी। ये देश के किसी भी अस्पताल में इलाज करा सकेगा।

मुख्यमंत्री रघुवर दास को नामकुम के बड़ाम में विधिक सेवा सशक्तीकरण शिविर एवं समावेशी न्याय सदन के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आज उत्सव का दिन है। राखी भई-बहन के प्रेम का पर्व है। झारखंड की तमाम बहनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है और मैं इसका संकल्प लेता हूँ। उन्होंने कहा कि सात नवंबर 2016 को समावेशी न्याय सदन का शिलान्यास हुआ और 21 माह बाद इसका उद्घाटन हुआ।

झारखंड के 26 किसान इजराइल रवाना | पढ़ें पेज 4 पर

दिव्यांग दशरथ को दिया राशन कार्ड तो पूछा-दुकान कैसे जाएंगे, मुख्यमंत्री ने तुरंत दिया व्हील चेयर



दिव्यांग दशरथ नायक को मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राशन कार्ड दिया। दशरथ ने पूछा-हुकूमत राशन दुकान तक कैसे जाएंगे। सीएम ने बीसी से लकड़ल व्हील चेयर मंगाया और दशरथ को दे दिया। इस मौके पर झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस जोगेन प्रताप और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश मौजूद थे।

चीफ जस्टिस बोले-समावेशी न्याय लिटिगेशन कम करने में सफल होगा : झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने कहा कि समावेशी न्याय लिटिगेशन को कम करने में सफल होगा। लघु ही लघु के विरुद्ध और अतीव लघु को न्याय और जस्टिस तक ले जाने पर सफल होगा।

हरिवंश ने कहा-समावेशी न्याय सदन ऐतिहासिक कदम : राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि समावेशी न्याय सदन एक ऐतिहासिक कदम है। कानून और न्याय आज अग्रणी के रूप में सामने लक्ष्य हैं। वहीं झारखंड के कार्यकारी चेंबरमैन जस्टिस टीरु प्रताप ने कहा कि लोका अदालत के माध्यम से स्थिति न्याय मिलना है।

दैनिक जागरण

दि. 27 अगस्त 2018

राजधानी जागरण

न्याय सदन का उद्घाटन, गरीबों को निशुल्क कानूनी सहायता

न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका **तीनों मिलकर** करेंगे समस्याओं का समाधान

राज्य सचिव, सीपी। मुखर्जी ने शुक्रवार रात ने कहा कि लोकतंत्र की सफलता तभी संपन्न होगी जब अधिकारपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के समन्वय से विकास को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना संभव है। सीएम ने परिवार को आश्रय, आश्रुत में अक्षयिनी विधिक सेवा समर्थन एवं परिवार एवं समावेशी न्याय सदन के उद्घाटन के अवसर पर यह बातें कहीं। यहां गरीबों को नि:शुल्क कानूनी सहायता मिल सकेगी। इस न्याय सदन के माध्यम से न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों का समन्वय से उनके अधिकारों को उपस्थिति में जल्दी से कर ही सकेगा।

मुखर्जी ने कहा कि लोकतंत्र की सफलता के लिए हम सब की जिम्मेदारी है, कि सभी समन्वय से कार्य करके जल्दी से विकास को प्राप्त करें। कानून, आज समाधान के सबसे बड़ा साधन है। 7 नवंबर 2016 को सामाजिक न्याय सदन का गठन हुआ था और 21 माह बाद इसका उद्घाटन हो रहा है। सीएम ने इसके लिए राज्य सरकार, परिवार, न्यायपालिका और प्रशासन के अधिकारी, पंचायत समितियों, जिला स्तर पर न्याय सदन को भी कहा है। इसका माध्यम से विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। मुखर्जी ने कहा कि एक वर्ष में यह पहला अक्षयिनी से उद्घाटन की प्रतिक्रिया को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इस उद्घाटन से 20 लाख लोग लाभान्वित होंगे और 1,60,598 लोग और लाभान्वित हो सकेंगे।

सीएम ने कहा, अधिक लोक विकास पहुंचाना सभी लोकतंत्र सफल

25 विचार को ध्यान कर सकते हैं न्याय सेवा योजना का शुभारंभ



विधिक सेवा सह समर्थन-कारण विधिक एवं समावेशी न्याय सदन के उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री को विद्वित पर देते मुखर्जी ने शुक्रवार रात और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अतिरिक्त बोस। साथ में हैं राज्य सचिव के उपसचिव अश्विनी - मुखर्जी

किराने क्या कहा
समावेशी न्याय सदन एक ऐतिहासिक क्षण है तथा इतना बड़ा प्रयास करने की शक्ति। कानून और न्याय, आज समाजी के लिए माध्यम बन रहा है।
- अश्विनी, राज्य सचिव के उपसचिव

समावेशी न्याय विधि-सदन को काम करने में सफल होगा। साथ ही सबसे बड़े और गरीब लोगों को न्याय और विकास तक ले जाने का माध्यम होगा।
- अतिरिक्त बोस, मुख्य न्यायाधीश

हजार रुपये सीपी उनके छात्रों में कर रहे। प्रशासन के कार्यकारी पंचायत समितियों और गरीबों को न्याय और विकास तक ले जाने का माध्यम होगा।
- अतिरिक्त बोस, मुख्य न्यायाधीश

केरल के लिए खाना की गई सहत सामग्री
इस मौके पर केरल के लिए न्याय प्रशासन तैयारी द्वारा सहत के लिए, 'जलसेवा' समर्थन के एक टुक के मुख्यमंत्री ने न्याय किया। इस मौके पर न्यायपालिका विभाग की और से राज्य-सचिवों को करीब 10 करोड़ रुपये की उपकरणों भी प्रदान की गईं। विचारों को दान समर्थन से लेकर केरल के लिए सब सालन और कृषि उत्पादन भी विचारित किए गए।

अवसर पर इतराई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा अतिरिक्त एवं कड़ी संकेत में समीक्षा उपस्थित थे।
समावेशी विचारों में भारी भरकाने महारों के भाई की सीपी विधायक पर। इस मौके पर उद्घाटन विचार में भारी

राजको मिलेगी स्वास्थ्य सुविधा मुखर्जी ने कहा कि पहिले उद्घाटन उपस्थित की अपनी 25 विचारों से पूरे देश में अनुभव प्राप्त योजना की सुव्यवस्था हो गई है। इतराई भी इससे सुदृढ़ता के लिए सचिव है। सीएम ने कहा कि इससे कठिन होगी कि प्रशासन में न्याय सेवा 25 विचार को इतराई को करती से विचार को सबसे बड़े समाधान को प्राप्त कर सुधारण करें। इस योजना का लाभ इतराई के 50 लाख परिवार को मिलेगा। सबसे बड़ा न्याय सुविधा मिले यह सचवा पूरा होगा।

समावेशी न्याय सदन में मिलेगी ये सुविधाएं
विधिक सेवा, प्रशासन, एक ही लोक अदालत, प्रत्येक, मुख्य न्यायाधीश, विधिक विभाग, समाधान केन्द्र, सुविधा का प्रावधान, विधिक उपस्थित, मुख्य न्यायाधीश, प्रशासन, राज्य, ई-सेवा एवं इतराई सुविधा, लीडरशिप टेलीफोन सुविधा, एनडीडी एवं सीआरए, एक कठिन विचारित न्याय सुविधाएं।

एक करोड़ महारों के अक्षयिनी आई मनोज महारों को अक्षयिनी के अवसर पर सुविधा एवं से केंद्र के लिए विधिक सेवा प्रदान किया गया। वहीं, न्यायपालिका में भारी भरकाने के विचारों को 50-50 हजार रुपये की सहायता मिले भी हो गई।